



www.agrabharat.in

अग्रभारत

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19

अंक: 117

आगरा, गुरुवार 15 अक्टूबर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 ₹.

सीजेपी नेता दिपके, सौरभ और आशुतोष इनकी कमाई का क्या है जरिया?

नई दिल्ली,(ए)। काँकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। बाद में 50,000 की जमानत सह व्यक्तिगत बॉन्ड भरने के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। इन तीनों को सीजेपी के मुख्य चेहरों के तौर पर जाना जाता है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसने सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता हासिल की है।

सीजेपी के संस्थापक के तौर पर पहचाने जाने वाले अभिजीत दीपके एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रणनीतिकार और पत्रकार हैं। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की डिजिटल मीडिया टीम के साथ काम किया और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन सलाहकार के तौर पर सेवा दी। यह भूमिका है दीपके की आजीविका के लिए उनके पेशेवर बैकग्राउंड को दर्शाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौजूदा सैलरी, निजी कमाई या फिर संगठन में उनके व्यक्तिगत योगदान की राशि का कहीं



भी जिक्र नहीं है।

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार और सूचना का अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वे खोजी पत्रकारिता और अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिखकर कमाते हैं। सौरभ दास ने कहा

कि आंदोलन को स्थापित करते समय सदस्य अपनी बचत और कमाई पर निर्भर थे। उनकी व्यक्तिगत पेशेवर इनकम और समूह के साथ साझा खर्च अलग-अलग मामले हैं। उनकी कमाई या फिर सीजेपी गतिविधियों पर उनके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए कोई खास आंकड़ा नहीं दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिकार और प्रवक्ता आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने लंदन में मैकिन्से में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है। इसके साथ वे दिल्ली असंबली फैलोशिप और राजस्थान में जनहित से जुड़े कामों में भी जुड़े रहे हैं। यह जानकारी उनकी

शिक्षा और प्रोफेशनल अनुभव के बारे में बताती है, लेकिन इससे उनके मौजूदा रोजगार या फिर अभी की कमाई का पता नहीं चलता। मौजूद जानकारी में सैलरी, निजी संपत्ति का अनुमान या फिर सीजेपी को दिए जाने वाले किसी भी आर्थिक योगदान का ब्योरा नहीं दिया गया है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सीजेपी अपनी गतिविधि का खर्च उत्र कैसे रही है।

सौरभ दास ने कहा है कि इन संसाधनों से ग्रुप की गतिविधि के शुरुआती दौर में खर्च उठाने में मदद मिली। नेताओं ने इस बात का भी जिक्र किया है कि सीजेपी का कोई रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नहीं है और उसे विदेशी फंडिंग नहीं मिलती है। उनका कहना है कि कार्यक्रमों का खर्च विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर रखे डोनेशन बॉक्स, आम लोगों से मिलने वाले छोटे-मोटे स्वीच्छिक योगदान और शुभचिंतकों से मिलने वाली मदद से पूरा किया जाता है। ग्रुप की फंडिंग के बारे में जानकारी उसके नेताओं की निजी बचत, जन-दान और सामान के रूप में मिली मदद के बयानों पर आधारित है। कहीं पर भी विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड, इकट्ठा की गई रकम या खर्च का ब्योरा नहीं दिया गया है।

आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा

नई दिल्ली(ए)। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास को दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में जबरन घुसने के मामले में पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत, पार्टी के एक अन्य सदस्य अभिजीत दीपके के राजनीतिक गुरु अजिंक्य शिंदे को हालांकि पीस बॉन्ड भरवाकर रिहा कर दिया गया। इससे पहले रांका, सौरभ दास और शिंदे सहित तीनों नेताओं को बीते कल हिरासत में लिया गया था। आज सुबह उन्हें ह्दतिथात गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां शिंदे को छोड़कर दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

रांका और दास को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले पर काँकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दोनों का गुनाह क्या था? उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा, आशु और सौरभ को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी क्या गलती है? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना?पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तीनों नेताओं को मंगलवार तड़के उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वे बैरिकेडिंग पार कर जंतर-मंतर क्षेत्र में घुस गए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शनों के लिए अधिसूचित स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने तीनों के खिलाफ जबरन प्रवेश करने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, शांति बनाए रखने के लिए दिए गए मुचलके की शर्तों का उल्लंघन करने और लोक सेवक को उसके अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है।

काँकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त पर चुनावों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। हाल के दिनों में जंतर-मंतर पर उनके आंदोलन के कई प्रयासों को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया है।दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने 11 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल घोषित किया था। इसके बाद जंतर-मंतर को निर्धारित धरना स्थलों की सूची से हटा दिया गया। सीजेपी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदर्शनों को राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक केंद्र से दूर ले जाने से लोगों के विरोध की आवाज कमजोर होगी।

3 और कलवरी क्लास सबमरीन का निर्माण करेगा भारत, लागत होगी 33,000 करोड़



नई दिल्ली,(ए)। भारतीय नौसेना की सबमरीन ताकत बढ़ाने के लिए 3 और कलवरी क्लास सबमरीन बनाने की तैयारी की जा रही है। इन सबमरीन का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में फ्रांस की नेवल ग्रुप की मदद से किया जा सकता है। इनकी अनुमानित लागत करीब 33,000 करोड़ बताई गई है। भारतीय नौसेना के पास पहले से 6 कलवरी क्लास सबमरीन हैं। ये डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें समुद्र में दुश्मन के जहाजों और सबमरीन का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर हमला करने जैसे कामों के लिए बनाया है।

नौसेना के सामने पुरानी सबमरीन को धीरे-धीरे बदलने और अपनी ताकत बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में तीन और कलवरी क्लास सबमरीन का प्रस्ताव मौजूदा क्षमता को बनाए रखने की योजना का हिस्सा है। इससे देश में

सबमरीन बनाने का काम भी जारी रह सकता है। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा बनाए रखना अहम है। पाकिस्तान चीन की मदद से हंगेर क्लास की मॉर्डन सबमरीन हासिल कर रहा है। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्मल डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में पानी के अंदर ज्यादा समय तक रहने में मदद करती है। भारत और पाकिस्तान की सबमरीन की क्षमता की तुलना केवल उनकी संख्या से नहीं की जा सकती। हथियार, सेंसर, ट्रेनिंग और रखरखाव जैसे कई पहलू भी अहम होते हैं।

कलवरी क्लास सबमरीन में पहले के मुकाबले बेहतर तकनीक और मॉर्डन वेपन सिस्टम शामिल किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक इनमें नए टॉरपीडो और मिसाइलों को शामिल करने की प्लान पर विचार किया जा रहा है। इन सबमरीन के प्रोडक्शन

से मझगांव डॉक और उससे जुड़ी भारतीय कंपनियों को भी काम मिल सकता है। इससे देश में पनडुब्बी निर्माण का अनुभव और तकनीकी कौशल का अनुभव और तकनीकी कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत 6 मॉर्डन सबमरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75(आई) पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की कंपनी थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ सहयोग की योजना है। इन सबमरीन में एआईपी तकनीक शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे वे लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकेंगे। दोनों योजनाओं की प्रगति और अंतिम समय-सीमा सरकारी मंजूरी और डील पर निर्भर करेगी। सबमरीन समुद्र में निगरानी, दुश्मन के जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हमले की क्षमता देती हैं। इसलिए नौसेना के लिए पर्याप्त संख्या में आधुनिक सबमरीन बनाए रखना अहम है।

उप्र में सपा-कांग्रेस गठबंधन का सीट बंटवारा लगभग तय

लखनऊ(ए)। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग अंतिम रूप ले चुका है। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच प्रारंभिक दौर की बातचीत हो चुकी है, और जल्द ही सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। इस समझौते के तहत, कांग्रेस के कुछ दावेदार सपा के चुनाव चिन्ह साफ़िल पर चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से कांग्रेस की पुरानी और परंपरागत सीटों पर अपनाया जा सकता है, जिससे गठबंधन की मजबूती बढ़ाई जा सके। सूत्रों के अनुसार, इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी बड़े भाई और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। सीटों का बंटवारा इस सिद्धांत पर आधारित होगा कि जिस क्षेत्र में जो दल अधिक मजबूत होगा, उसकी दावेदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में पुराने गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। इस रणनीति का मुख्य आधार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली अभूतपूर्व सफलता है। उस चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर प्रदेश की 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को पीछे छोड़ दिया था। सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जो दोनों दलों के लिए एक बड़ी वापसी थी।

हालांकि, पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को निराशा हाथ लगी थी। तब सपा 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन दोनों को मिलाकर केवल 54 सीटें ही मिल पाई थीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी और केवल दो सीटें जीत सकी, जबकि उसके अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। सपा ने उस चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 111 सीटें जीती थीं। इस बार समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत और मजबूत सीटों पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इन सीटों पर सपा ने अपने संभावित उम्मीदवारों को पहले ही क्षेत्र में सक्रिय होकर चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद, सपा इस विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और इसकी घोषणा के लिए जल्द ही दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है।

जम्मू-कश्मीर: मस्जिदों में ‘एकसमान खुतबे’ का फरमान

जम्मू,(ए)। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा घाटी की मस्जिदों और दरगाहों में शुक्रवार के जुमा के भाषण (खुतबे) के लिए एक समान थीम लागू करने के प्रयासों ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस कदम का घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोरदार विरोध किया है, इसे मुस्लिम धार्मिक स्थलों और उनकी आजादी पर केंद्र सरकार और भाजपा की नियंत्रण की साजिश करार दिया जा रहा है। इस पूरे विवाद ने कश्मीर में धार्मिक विमर्श और उपदेशों को तय करने के अधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें एक तरफ भाजपा नेता दरखाश अंद्राबी की अध्यक्षता वाला वक्फ बोर्ड है तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का पारंपरिक और स्थापित इस्लामिक नेतृत्व है।भाजपा नेता दरखाश अंद्राबी की अध्यक्षता वाला वक्फ बोर्ड, हजततबल सहित घाटी की कई प्रमुख दरगाहों और मस्जिदों का संचालन करता है।

नीला ड्रम हत्या केस: मुस्कान और साहिल को फांसी

मेरठ(ए)। बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी ठहराई गई मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आज अदालत सजा सुनाएगी। 30 सितंबर को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों के भाग्य का फैसला आज होगा, जब कोर्ट उनकी सजा का ऐलान करेगा। पीड़ित परिवार ने जहां आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है, वहीं जेल प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

सजा सुनाए जाने से ठीक पहले मुस्कान और साहिल की बेवैनी बह गई है। जेल

अधीक्षक के अनुसार, दोषी करार दिए जाने के बाद से दोनों शांत रहने लगे हैं और उनकी बातचीत भी कम हो गई है। मुस्कान ने पूजा-पाठ भी घटा दिया है। उनके तनाव और अवसाद को देखते हुए चिकित्सकीय परीक्षण और

नियमित काउंसलिंग कराई जा रही है। जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ा दी है। मुस्कान अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उसने जेल प्रशासन से अपनी बड़ी बेटी पीहू से मुलाकात या फोन पर बात कराने की मांग की थी,

अपने घर पर पूजा-पाठ भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यह खौफनाक वारदात 3 मार्च 2025 को रात को ब्रह्मपुरी में हुई थी। मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश किया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। निर्मम हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में भरा गया और सीमेंट से जमा दिया गया। वारदात को

लेकिन मोबाइल नंबर उपलब्ध न होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। मुस्कान ने अपनी बेटी के लिए एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरी ओर, मृतक सौरभ राजपूत का परिवार

अंजाम देने के बाद 4 मार्च को मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश फरार हो गए थे, जहां से उन्हें 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद ही सौरभ की लाश ड्रम से बरामद की गई थी।

दो सरकारों की नींव हिलाने का साक्षी है रामलीला मैदान

नई दिल्ली(ए)। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों की राजनीति में एक बार फिर रामलीला मैदान का नाम प्रमुखता से उभरा है। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के बाद दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान को तीन वैकल्पिक जगहों में से एक के रूप में तय किया है। यह फैसला मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच आया है। हालांकि जंतर-मंतर लंबे समय से प्रदर्शनों का केंद्र रहा है, रामलीला मैदान का इतिहास भी आंदोलनों और बड़े राजनीतिक बदलावों का साक्षी रहा है। दशकों के अंतराल में इस मैदान पर दो ऐसे बड़े जन आंदोलन हुए, जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इनमें पहला आंदोलन 1975 में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में उठ था। 25 जून 1975 को जेपी ने इसी मैदान से एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान किया था। इसी रात देश में आपातकाल लगा दिया गया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हुईं और विपक्ष पर कार्रवाई हुई। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को



केंद्र में पहली बार हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी सत्ता में आई। इस तरह रामलीला मैदान में हुई यह रैली भारतीय राजनीति के एक बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ गई। करीब 36 साल बाद 2011 में था। 25 जून 1975 को जेपी ने इसी मैदान से एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान किया था। इसी रात देश में आपातकाल लगा दिया गया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हुईं और विपक्ष पर कार्रवाई हुई। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रातिनिधील गठबंधन (यूपीए) सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरी थी, और अन्ना बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ गई। करीब 36 साल बाद 2011 में था। 25 जून 1975 को जेपी ने इसी मैदान से एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान किया था। इसी रात देश में आपातकाल लगा दिया गया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हुईं और विपक्ष पर कार्रवाई हुई। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को

8वें वेतन आयोग: कब से मिलेगा कर्मचारियों को एरियर?

नई दिल्ली,(ए)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, खासकर सैलरी रिवीजन और एरियर को लेकर। कर्मचारी चाहते हैं कि नया पे स्केल 1 जनवरी 2026 से लागू हो, लेकिन इसकी अंतिम तारीख और एरियर के भुगतान का फैसला अभी बाकी है। पिछले वेतन आयोगों का इतिहास बताता है कि एरियर की गणना और भुगतान की तारीख कर्मचारियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। 5वें और 6वें वेतन आयोग में बड़े पैमाने पर एरियर का भुगतान किया गया था, जबकि 7वें वेतन आयोग ने पैदा होने वाले आर्थिक दबाव को कम रखने की कोशिश की थी। 5वें वेतन आयोग के तहत एरियर का भुगतान दो वित्तीय वर्षों - 1997-98 और 1998-99 में हुआ था। एरियर भुगतान के कारण सरकारी खर्च पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के लिए, रक्षा क्षेत्र में वेतन और भत्तों का हिस्सा कुल रक्षा राश्व खर्च में लगभग 40-41 से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया था। इसी तरह, 6ठे वेतन आयोग में भी एरियर का भुगतान सरकार के लिए एक बड़ा खर्च साबित हुआ, जिससे राजकोषीय स्थिरता और कीमतों पर भी अस्थायी असर पड़ने की आशंका थी। इसके विपरीत, 7वें वेतन आयोग ने अपने सैलरी रिवीजन की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2016 रखने की सिफारिश की थी, जबकि कर्मचारी संगठन इसे 1 जनवरी 2014 से लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसे आयोग ने स्वीकार नहीं किया।

7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिसमें उस समय के 125प्रतिशत महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में एडजस्ट करने के बाद वास्तविक इंडीमेंट करीब 14.2 प्रतिशत बैठती थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए, कर्मचारी 1 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसकी मुख्य वजह पिछले वेतन आयोगों के 10 साल के चक्र के आधार पर इस तारीख से नए सैलरी रिवीजन के प्रभावी होने की संभावना पर चर्चा है। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिससे रिपोर्ट मई 2027 के आपरास आने की उम्मीद है। इसके बाद भी, सरकार द्वारा समीक्षा, मंजूरी और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। यदि सरकार सैलरी रिवीजन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी घोषित करती है, तो उस तारीख से लागू होने के समय का एरियर बन सकता है। हालांकि, इसकी सटीक गणना नए पे स्केल, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों और सरकार के अंतिम नियमों पर निर्भर करेगी। कर्मचारियों को अभी अंतिम निर्णय का इंतजार है।